ई संदेश

10 सितम्बर, 2026 | अंक - 222

सात दिन, सात पृष्ठ

- बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार, गंगा ड्रेजिंग से होगा समस्या का स्थायी समाधान : मुख्यमंत्री
- विरासत और विकास के समन्वय से संवर रही ब्रजभूमि : मुख्यमंत्री
- ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास और विरासत संरक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं : मुख्यमंत्री
- बाढ़ पीड़ितों को हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री ने जनपद चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित 800 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की
- बाढ़ प्रभावितों को पारदर्शी ढंग से मिले राहत, मंदाकिनी के अतिक्रमण पर करें प्रभावी कार्रवाई : मुख्यमंत्री
- उत्तर प्रदेश को आधुनिक तकनीक और निवेश से वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में किया जाएगा विकसित: मुख्यमंत्री
- सुपोषित बचपन और सशक्त मातृत्व से ही विकसित भारत का निर्माण: मुख्यमंत्री
- आधी आबादी को हो महिला सशक्तिकरण का वास्तविक एहसास: मुख्यमंत्री

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार, गंगा ड्रेजिंग से होगा समस्या का स्थायी समाधान : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 03 सितम्बर, 2026 को जनपद फर्रुखाबाद की तीनों बाढ़ प्रभावित तहसीलों—सदर, कायमगंज और अमृतपुर का स्थलीय व हवाई सर्वेक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित 102 गांवों के नागरिकों के प्रति प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। आपदा की इस विषम परिस्थिति में डबल इंजन की सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है और आवश्यकतानुसार हर सम्भव मदद पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रभावित परिवारों को लगभग 50 किलोग्राम की विशेष राहत सामग्री किट, आपदा मोचक निधि से आर्थिक सहायता तथा बेघर हुए लोगों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। जिन परिवारों के घर बाढ़ में नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे कंट्रोल रूम, राहत चौकियां और शिविर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर तत्काल कार्ययोजना तैयार की जाए। बाढ़ का पानी उतरते ही लोक निर्माण विभाग (पी0डब्ल्यू0डी0) द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की युद्ध स्तर पर मरम्मत कराई जाए, ताकि जनसामान्य का आवागमन बाधित न हो। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षकों द्वारा राहत शिविरों में अलग से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गंगा नदी के उथले होने के कारण पानी का फैलाव होता है, जिससे व्यापक फसल क्षति होती है। इसके स्थायी समाधान हेतु पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की ड्रेजिंग कराकर उसे चैनलाइज किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि ड्रेजिंग से निकलने वाली सामग्री का उपयोग सुदृढ़ तटबन्ध बनाने में किया जाए। इस परियोजना में यदि किसानों की भूमि उपयोग में आती है, तो उन्हें पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जलभराव को देखते हुए संक्रामक रोगों तथा सर्पदंश आदि से बचाव के लिए सभी सी0एच0सी0 और जिला चिकित्सालयों में एंटी-वेनम, एंटी-स्नेक वेनम, एंटी-रेबीज वैक्सीन व आवश्यक दवाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त, पशुधन की सुरक्षा के लिए चारे, दवाओं और टीकाकरण के भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फर्रुखाबाद में विकास की गति तेज हुई है। यहां गंगा एक्सप्रेस-वे का लिंक एक्सप्रेस-वे निर्मित हो रहा है, जो इसे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगा। बेहतर सड़कों और सुदृढ़ कनेक्टिविटी के कारण बाढ़ जैसी आपदा में भी अधिकांश गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से बना हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि फर्रुखाबाद प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र है। कोल्ड स्टोरेज में उत्पाद रखने वाले किसानों के भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मक्का खरीद के लिए क्रय केंद्र तथा आगरा में पेरू के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का रीजनल सेंटर स्थापित कर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों का त्वरित सर्वे कराया जाए। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रभावित अन्नदाता किसानों को डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में राहत राशि भेजी जाएगी।

विरासत और विकास के समन्वय से संवर रही ब्रजभूमि : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 03 सितम्बर, 2026 को जनपद मथुरा में स्वामी श्री हरिदास प्रेक्षागृह सहित 1,051 करोड़ रुपये लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने पूज्य संतों का सम्मान करने के साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र, नियुक्ति पत्र, आवास व ट्रैक्टर की चाभी और टूल किट प्रदान किए। मुख्यमंत्री जी ने विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, महिलाओं की गोदभराई व बच्चों का अन्नप्राशन कराया, पुस्तक 'ईकोज ऑफ डिग्निटी' का विमोचन किया तथा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पारिजात का पौधा रोपित किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी स्मृति, संस्कृति और जड़ों से जुड़कर ही महान बनता है। जिस समाज को अपनी विरासत का ज्ञान होता है, वह दुनिया से सीखता भी है और दुनिया को सिखाता भी है। ब्रजभूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, भक्ति, संगीत, लोक कला और आध्यात्मिक परम्परा का जीवन्त केन्द्र है। महान संत स्वामी हरिदास जी ने भक्ति को संगीत और साधना से जोड़कर समाज की चेतना को जागृत किया। उनकी साधना से प्रभावित होकर महान संगीतज्ञ तानसेन उनके शिष्य बने और मुगल सम्राट भी भक्ति रस से जुड़ने को प्रेरित हुए।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लम्बे समय तक विकास को केवल भौतिक निर्माण तक सीमित रखा गया और विरासत की उपेक्षा की गई। विदेशी आक्रांताओं ने सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट करने के कुत्सित प्रयास किए, लेकिन वे सनातन की जीवन्त चेतना को समाप्त नहीं कर सके। मथुरा, काशी और अयोध्या जैसे पावन धाम इसके जीवन्त प्रमाण हैं। काशी में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर द्वारा पुनर्निर्माण और वर्तमान में काशी विश्वनाथ धाम का विकास तथा अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण सनातन परम्परा की अनवरत निरंतरता को प्रदर्शित करता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार 'विरासत भी और विकास भी' तथा 'आस्था भी और अर्थव्यवस्था भी' के मंत्र पर कार्य कर रही है। विकास की पहली अनिवार्य शर्त कानून का राज है। प्रदेश अब कर्फ्यू, दंगा और भय से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। जिस मथुरा में वर्ष 2016 में जवाहरबाग जैसी दुखद घटना हुई थी, आज वही मथुरा लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है। सुरक्षा और सुदृढ़ व्यवस्था के चलते ही वर्ष 2025 में प्रदेश में रिकॉर्ड लगभग 156 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ तथा प्रयागराज महाकुम्भ में 66 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य स्मार्ट सिटी मिशन और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का सर्वांगीण विकास तीव्र गति से हो रहा है। विगत आठ वर्षों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। 84 कोसी, पंच कोसी व वन परिक्रमा मार्गों का उन्नयन, ऐतिहासिक कुण्डों का जीर्णोद्धार, रोप-वे, मेगा पार्किंग तथा राया अर्बन नोड जैसी आधारभूत परियोजनाएं आधुनिक भविष्य की मजबूत नींव रख रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्रज भाषा और साहित्य के संरक्षण हेतु 'सूरदास ब्रज भाषा अकादमी' की स्थापना की गई है तथा स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव से कलाकारों को वैश्विक मंच मिला है। इसके साथ ही वृन्दावन में 400 एकड़ क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े सिटी फॉरेस्ट 'सौभरि वन' को विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विकास का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के तहत घुमन्तू व सपेरा समुदाय के उपेक्षित परिवारों को आवासीय पट्टे एवं पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और सरकार ब्रज क्षेत्र को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त तीर्थ के रूप में स्थापित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास और विरासत संरक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 03 सितम्बर, 2026 को जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की नवीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास, विरासत संरक्षण एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा का कार्य आगामी 03 वर्षों में 03 चरणों में पूर्ण किया जाएगा तथा मथुरा-वृन्दावन रेल मार्ग पर सड़क मार्ग निर्माण की योजना पर भी सहमति बन गई है। इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री जी ने कान्हा भक्ति स्तम्भ मार्ग का लोकार्पण कर स्थलीय निरीक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिला प्रशासन, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय स्थापित कर ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार करें, जिससे धरातल पर व्यापक परिवर्तन दिखाई दे। उन्होंने वृन्दावन नगर में नए सिटी बस मार्ग के सृजन के संदर्भ में स्थानीय मार्गों के अनुकूल वाहनों के संचालन के निर्देश दिए। साथ ही प्राचीन ज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहरों की वाहक पाण्डुलिपियों के व्यवस्थित संरक्षण पर विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ-साथ उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा पूर्व से स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने मथुरा-वृन्दावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह होल्डिंग एरिया विकसित करने, पार्किंग क्षमता का विस्तार करने तथा डॉरमेट्री, कैफे व फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त मल्टीलेवल पार्किंग व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्किंग परियोजनाओं को रेवेन्यू शेयरिंग अथवा पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किया जाए, जिससे आम जनमानस को सुगम सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पौराणिक कुण्डों, ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार संतुलित मैनपावर के उपयोग तथा जनहित के उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों व सफलता की कहानियों का मीडिया व जनसंवाद के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वृन्दावन परिक्रमा मार्ग को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए और निर्माण में ऐसी गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग हो जिससे वर्षाकाल में फिसलन न हो और श्रद्धालुओं को चलने में असुविधा न हो। इसके साथ ही मथुरा के खारे पानी की समस्या के स्थायी समाधान हेतु अधिकाधिक तालाबों के निर्माण तथा वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) के माध्यम से भू-जल स्तर में सुधार लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दृष्टिगत पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए तथा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी निरंतर सतर्क रहें। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पर कर्मचारियों की 24 घंटे सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। वर्षाकाल के दृष्टिगत स्वच्छता व्यवस्था को चाक-चौबंद रखते हुए दो शिफ्टों में सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन तथा अपशिष्ट के त्वरित व वैज्ञानिक निस्तारण के प्रभावी प्रबंध किए जाएं।

बैठक में हार्टफुलनेस फाउंडेशन द्वारा सी0एस0आर0 मद से कार्य कराए जाने, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर 10 गोल्फ कार्ट दान दिए जाने, 'स्मारक मित्र' की तर्ज पर 'तीर्थ मित्र' योजना संचालित करने तथा परिषद के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण पर विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त, मथुरा-वृन्दावन में पुलिस बल बढ़ाने, महायोजना मार्गों के निर्माण तथा ब्रज की 200 चिन्हित जोखिमग्रस्त ऐतिहासिक धरोहर संरचनाओं के संरक्षण व प्रबंधन हेतु एक सुदृढ़ 'क्षेत्रीय विरासत प्रबंधन ढांचा' विकसित करने पर भी सहमति बनी।

बाढ़ पीड़ितों को हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 05 सितम्बर, 2026 को जनपद वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के उपरान्त विद्या विहार इण्टर कॉलेज में प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री जग्गू राम मौर्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा राहत शिविर का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की इस विषम घड़ी में प्रभावित नागरिक स्वयं को अकेला न समझें। डबल इंजन की सरकार हर पीड़ित के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है तथा 24 घण्टे संचालित कण्ट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गंगा जी के जलस्तर में वृद्धि के कारण वरुणा नदी में बैक फ्लो से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रदेश के 40 से 45 जनपद प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ की चपेट में आते थे, किन्तु विगत 09 वर्षों में प्रभावी बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के परिणामस्वरूप अब यह संख्या घटकर मात्र 14 जनपदों तक सीमित रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए काशी विश्वनाथ धाम, घाटों के पुनर्विकास, सुदृढ़ रिंग रोड तथा आधुनिक जनसुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वाराणसी के 16 वॉर्डों के 567 परिवारों के 2,486 नागरिक प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए 21 राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की गई है। बचाव व निगरानी कार्यों में एन0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0 और पुलिस की टीमें निरन्तर सक्रिय हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार को 26 प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से युक्त विस्तृत राहत किट उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि किसी भी नागरिक को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कठिनाई न हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाराणसी में लगभग 131 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हुई है, जिससे 1,129 किसान प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से फसल क्षति का सर्वेक्षण पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रभावित अन्नदाता किसानों को शीघ्र मुआवजा वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यदि किसी निर्धन परिवार का आवास क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुआ है, तो उसे पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सर्पदंश, आकाशीय बिजली, डूबने अथवा अन्य आपदा जनित दुर्घटनावश जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को 24 घण्टे के भीतर आपदा राहत निधि से निर्धारित आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बाढ़ के उपरान्त संक्रामक एवं जलजनित रोगों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नियमित मेडिकल कैम्प आयोजित कर निःशुल्क औषधियां दी जा रही हैं तथा वंचित पात्रों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि जलस्तर घटते ही युद्ध स्तर पर विशेष सफाई, सैनिटाइजेशन और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए, जिससे सामान्य जनजीवन निर्बाध रूप से शीघ्र बहाल हो सके।

मुख्यमंत्री ने जनपद चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित 800 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 06 सितम्बर, 2026 को जनपद चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा रामघाट व समीपवर्ती क्षेत्रों में हुई क्षति का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने बेघर हुए परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटन प्रमाण पत्र तथा आपदा मोचक निधि से राहत राशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि आपदा की इस घड़ी में चित्रकूटवासी स्वयं को अकेला न समझें। डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती से हर नागरिक के साथ खड़ी है तथा आवश्यकतानुसार प्रत्येक सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि चित्रकूट में अचानक भारी जलप्रवाह की सूचना मिलते ही त्वरित गति से एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 और पी0ए0सी0 की फ्लड यूनिटों की आठ अतिरिक्त कम्पनियों को चित्रकूट रवाना किया गया, जिन्होंने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर जलमग्न घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। उन्होंने बताया कि चित्रकूट में विगत वर्ष जहां 360 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, वहीं इस बार एक ही दिन में 660 मिलीमीटर से अधिक अप्रत्याशित वर्षा हुई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में पानी आने के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर चार-चार मंजिल तक पहुंच गया और आवागमन हेतु बना पक्का पुल तक बह गया। भगवान श्रीराम, कामदगिरि, हनुमान जी की कृपा और संतों की तपस्या से इस भीषण विभीषिका में भी कोई जनहानि नहीं हुई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नदी के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण और अनियंत्रित निर्माण से बचना होगा तथा नदी के स्वाभाविक प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलभराव से घिरे नागरिकों को तत्काल सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया जाए, जहां उनके लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षा और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहें।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व आपदा राहत के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को लगभग 50 किलोग्राम वजन की 26 प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से युक्त डिग्निटी किट उपलब्ध करा रही है। इसमें आटा, चावल, दाल, आलू, तेल, मसाले, लाई-चना, बाल्टी, मग और बरसाती आदि आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि यदि बाढ़ अथवा आपदा में किसी निर्धन का मकान नष्ट हुआ है, तो उसे पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल नया आवास और भूमि का पट्टा बिना किसी विलम्ब के स्वीकृत किया जाए। इसके साथ ही डूबने, आकाशीय बिजली गिरने अथवा मानव-वन्यजीव संघर्ष में जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को 24 घण्टे के भीतर आपदा राहत निधि से 04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जलभराव के दृष्टिगत सभी सी0एच0सी0 और जिला चिकित्सालयों में एंटी-स्नेक वेनम तथा एंटी-रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे सर्पदंश अथवा जीव-जंतुओं के काटने पर तत्काल निःशुल्क उपचार मिल सके।

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से हुई फसल क्षति का पारदर्शी सर्वेक्षण शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि सीधे खातों में उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, घाटों, पुल-पुलियों तथा विद्युत पोलों व तारों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आम नागरिकों के साथ-साथ व्यापारियों, आश्रमों, मठ-मंदिरों व अन्य संस्थानों को हुए नुकसान की भरपाई भी संवेदनशीलता के साथ की जाएगी। चित्रकूट की पावन तपोभूमि ने वनवास काल में प्रभु श्रीराम को आश्रय दिया था, अतः संकट की इस घड़ी में चित्रकूटवासियों के पुनर्वास और क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए सरकार पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही है।

बाढ़ प्रभावितों को पारदर्शी ढंग से मिले राहत, मंदाकिनी के अतिक्रमण पर करें प्रभावी कार्रवाई : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 06 सितम्बर, 2026 को जनपद चित्रकूट में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाढ़ की स्थिति, राहत व बचाव कार्यों, पुनर्वास एवं विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील कर्वी के प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 35,000 लंच पैकेट, 4,500 राशन किट तथा 650 बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रेषित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित व्यापारियों, संतों एवं किसानों की क्षति का त्वरित सर्वे कराकर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाए और नियमानुसार शीघ्र सहायता प्रदान की जाए। किसानों की फसल क्षति का सर्वेक्षण शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाए। पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के पात्र परिवारों को पट्टे की भूमि व नया आवास तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र प्रभावित परिवारों को विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध राहत किट की समीक्षा करते हुए शेष सभी किटों का वितरण 48 घण्टे के भीतर प्रत्येक पात्र परिवार तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री की गुणवत्ता उच्चस्तरीय रखी जाए और वितरण में पूर्ण निष्पक्षता बरती जाए।

मुख्यमंत्री जी ने मंदाकिनी नदी एवं उसके तटीय क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले पानी के सुगम निकास के लिए नदी का प्राकृतिक विस्तार आवश्यक है, क्योंकि नदी के संकरे होने से बाढ़ का खतरा बढ़ता है। भविष्य में आपदा से बचाव के लिए एक स्थायी एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार घाटों से सटे मठ-मंदिरों को पीछे स्थानांतरित करने के विकल्पों पर विचार करने तथा नदी पर बने पुलों की निर्माण गुणवत्ता व संरचनात्मक स्थिति का तकनीकी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त मठों, मंदिरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर आवश्यक होने पर मध्य प्रदेश शासन से समन्वय स्थापित करने को कहा।

मुख्यमंत्री जी ने देवांगना एयरपोर्ट से कर्वी तक 04-लेन सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। वर्ष 2023 में स्वीकृत तथा वर्ष 2024 में पूर्ण होने वाली इस परियोजना के लम्बित रहने पर उन्होंने 24 घण्टे में जांच रिपोर्ट तलब की। उन्होंने निर्देश दिए कि दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और संबंधित लापरवाह विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने नगर की स्वच्छता पर बल देते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती तथा नगर पालिका में स्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति हेतु पत्राचार के निर्देश दिए। उन्होंने नालों से अतिक्रमण हटाने, सड़कों व दुकानों से मलबा साफ कराने तथा सीवर व नालों के पानी का समुचित ट्रीटमेंट कर मंदाकिनी की निर्मलता बनाए रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को उपयुक्त स्थल चिन्हित कर सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए सर्पदंश एवं अन्य जीव-जंतुओं के काटने पर आवश्यक वैक्सीन व औषधियों की प्रचुर उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में 40 स्वास्थ्य टीमें, बाढ़ चौकियां, आशा व ए0एन0एम0 सक्रिय हैं तथा ब्लीचिंग व एंटी-लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि राहत शिविरों में रह रहे बच्चों की शिक्षा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों, विद्युत व्यवस्था व सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत हेतु नोडल अधिकारी नामित कर कार्य तत्काल शुरू कराए जाएं। इसके अतिरिक्त, पुलिस प्रशासन को क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग बढ़ाने और अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश को आधुनिक तकनीक और निवेश से वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में किया जाएगा विकसित: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 08 सितम्बर, 2026 को लखनऊ में दो दिवसीय कॉन्क्लेव 'यू0पी0 टेक्स-2026' का शुभारम्भ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल इण्डस्ट्री केवल आज की औद्योगिक गतिविधि नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध परम्परा, विरासत, हुनर और उद्यमिता का परिणाम है। प्रदेश के पास मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस, विशाल मानव संसाधन, देश का सबसे बड़ा बाजार, सुदृढ़ एम0एस0एम0ई0 नेटवर्क और विश्व का सबसे युवा वर्क फोर्स उपलब्ध है। 'यू0पी0' का अर्थ 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' बताते हुए उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र की इसी असीम क्षमता को आधुनिक तकनीक, निवेश, नवाचार और ग्लोबल मार्केट से जोड़कर प्रदेश को विश्व स्तरीय प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर यू0पी0 टेक्स मित्र पोर्टल, हथकरघा-बुनकर समृद्धि योजना तथा वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना का शुभारम्भ किया। साथ ही यू0पी0 टेक्सटाइल एवं गारमेण्टिंग पॉलिसी-2022 के अन्तर्गत उद्यमियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल0ओ0सी0) तथा प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने वस्त्र एवं परिधान उद्योग में ए0आई0 व डिजिटलीकरण की तैयारी से सम्बद्ध संयुक्त रिपोर्ट का विमोचन, प्रदर्शनी का अवलोकन और प्रमुख उद्यमियों के साथ राउण्ड टेबल संवाद किया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 'ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश इन्टू ए ग्लोबल टेक्सटाइल हब' थीम पर आधारित इस कॉन्क्लेव के माध्यम से 5,196 करोड़ रुपये के नये निवेश प्रस्तावों के 09 एम0ओ0यू0 संपन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त 163 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा 60 करोड़ रुपये की वित्तीय सब्सिडी का वितरण किया गया, जो दर्शाता है कि राज्य सरकार जो संकल्प लेती है, उसे धरातल पर क्रियान्वित करके दिखाती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वैदिक साहित्य में वर्णित 'हिरण्य वस्त्र', रामायण काल में काशी के दिव्य रेशमी व पीताम्बर वस्त्र तथा महाभारत में उल्लिखित सूती वस्त्र यह सिद्ध करते हैं कि प्रदेश की वस्त्र परम्परा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है। प्राचीन काल में रोम और ग्रीक सभ्यताओं तक उत्तर प्रदेश के वस्त्रों की व्यापक माँग रही है। आज वाराणसी की सिल्क, भदोही का कालीन, लखनऊ की चिकनकारी, कानपुर का टेक्सटाइल व लेदर, आगरा का अपैरल, सीतापुर का मैन्युफैक्चरिंग तथा मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स राज्य की विशिष्ट पहचान हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग 02 लाख हैण्डलूम और 05 लाख से अधिक पावरलूम बुनकर इस सेक्टर की वास्तविक रीढ़ हैं। देश के कुल फैब्रिक उत्पादन का 13 से 14 प्रतिशत निर्माण उत्तर प्रदेश में होता है और राज्य फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में देश में तीसरे स्थान पर है। पिछले 06 वर्षों में वस्त्र, परिधान व हस्तशिल्प निर्यात में 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है तथा राज्य देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल इकोनॉमी और 100 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2025-26 में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात के साथ गौतमबुद्धनगर देश में दूसरे स्थान पर रहा है। 35 से अधिक जनपदों के टेक्सटाइल उत्पादों को ओ0डी0ओ0पी0 से पहचान मिली है और 17 उत्पादों को जी0आई0 टैग प्राप्त हो चुका है। अब प्रदेश 'फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से गारमेण्ट, गारमेण्ट से ब्राण्ड और ब्राण्ड से ग्लोबल मार्केट' तक की सम्पूर्ण वैल्यू चेन विकसित कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति से कानून का राज स्थापित हुआ है। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के कारण निवेशकों का भरोसा सुदृढ़ हुआ है। राज्य में 75 हजार एकड़ का लैण्ड बैंक उपलब्ध है और 36 सेक्टोरल नीतियाँ प्रभावी हैं। विगत वर्षों में प्राप्त 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुके हैं, जिससे 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। इसके साथ ही देश की 55 प्रतिशत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेण्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पी0एम0 मित्र पार्क तथा संत कबीर टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से एकीकृत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित किए जा रहे हैं। वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर, बिजनौर, सीतापुर, कानपुर, मऊ, झाँसी और रायबरेली में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है, जबकि नोएडा को अपैरल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार प्रदेश को ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से आगे ले जाकर टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य 'डिजाइन्ड इन यू0पी0, मेड इन यू0पी0 एण्ड एक्सपोर्टेड फ्रॉम यू0पी0' के संकल्प के साथ स्थानीय हुनर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है। बुनकरों, उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक पूँजी में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

सुपोषित बचपन और सशक्त मातृत्व से ही विकसित भारत का निर्माण: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को जनपद वाराणसी में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के साथ 9वें राष्ट्रीय पोषण माह (09 सितम्बर से 08 अक्टूबर, 2026) का भव्य शुभारम्भ किया। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, बच्चों, किशोरियों तथा उनके परिवारों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल को समर्पित इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अवसर पर देशभर के 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र वर्चुअल माध्यम से जुड़े। शुभारम्भ से पूर्व मुख्यमंत्री जी एवं केन्द्रीय मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा महिलाओं की गोदभराई व बच्चों का अन्नप्राशन कराया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह को महज एक महीने का औपचारिक कार्यक्रम न मानकर सतत जन आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत, परिवार और समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़ा जाए। देश की वास्तविक शक्ति उसके युवाओं में निहित है और युवाओं का भविष्य उनके बचपन पर निर्भर करता है। स्वस्थ माँ और सुपोषित बच्चे से ही समर्थ, शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की सुदृढ़ नींव रखी जा सकती है। गर्भधारण से लेकर प्रथम 1,000 दिन बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अत्यंत निर्णायक होते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरा, माँ गंगा के आशीर्वाद और माता अन्नपूर्णा की कृपा से इस अभियान का आरम्भ होना विशेष महत्व रखता है। आदर्श शासन व्यवस्था ही रामराज्य है, जिसे रेखांकित करते हुए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन का उल्लेख किया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जिसमें कोई दरिद्र, दीन-हीन अथवा कमजोर न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और राष्ट्र निर्माण में सक्षम बने।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ व सहायिकाएँ जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और संस्कारों की वास्तविक अग्रदूत हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चा सुपोषित हो और परिवार पोषण को प्राथमिकता दें। सरकारें नीतियां बनाती हैं, किंतु योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का सबसे प्रामाणिक व भरोसेमंद माध्यम आंगनवाड़ी की बहनें हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2014 से पूर्व गरीबों और कुपोषितों का पोषण शासन की प्राथमिकताओं में उपेक्षित था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पोषण को राष्ट्रीय एजेंडे में शीर्ष स्थान मिला। गुजरात में रहते हुए उन्होंने जिस विजन को धरातल पर उतारा था, आज वही पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पोषण पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी उद्देश्य से प्रदेश की बाल वाटिकाओं में बच्चों को दो ड्रेस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, बैग व जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के क्रम में 40 वर्ष पुराने 2,100 विद्यालयों के भवनों हेतु आवश्यक धनराशि जारी की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्र जर्जर, बुनियादी सुविधाओं से वंचित और अनियमित पोषाहार आपूर्ति से जूझ रहे थे। विगत 09 वर्षों में राज्य के 70 हजार से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों का कायाकल्प करते हुए उन्हें आधुनिक व मॉडलकेन्द्रों में परिवर्तित किया गया है। प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र लगभग 30 लाख रुपये व्यय कर निर्माण, चहारदीवारी, शौचालय और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बाल वाटिकाओं के जरिए बच्चे खेल-खेल में पोषण व प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष के पोषण माह की थीम 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' जनसहभागिता का स्पष्ट संदेश देती है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के सशक्तिकरण हेतु प्रबंधन समितियों के गठन से समाज की जवाबदेही तय की जा रही है। अभियान के पाँच प्रमुख विषय—आहार विविधता व पर्याप्त प्रोटीन, ताजा एवं गर्म पका भोजन, सामुदायिक स्वामित्व, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से सहायता—निर्धारित किए गए हैं। बच्चों के भोजन में मौसमी सब्जियों का समावेश और नमक-चीनी का उचित संतुलन आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन के अनुरूप रेसिपी आधारित अनुपूरक पोषाहार व्यवस्था लागू की गई है। टेक होम राशन (टी0एच0आर0) व्यवस्था को तकनीक से जोड़ते हुए जीपीएस ट्रैकिंग और क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। टी0एच0आर0 की गुणवत्ता निगरानी के साथ-साथ 204 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन 20 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रदेश की 05 करोड़ माताओं को 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वीकृत 1 लाख 90 हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों और 897 बाल विकास परियोजनाओं के जरिए प्रतिमाह लगभग 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों तक पोषण सेवाएं पहुंच रही हैं। लगभग 35 लाख 46 हजार बच्चों को हॉट कुक्ड मील तथा 46 लाख बच्चों के पोषण स्तर की नियमित निगरानी की जा रही है। स्मार्टफोन के जरिए रियल टाइम डाटा फीडिंग से पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनी है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सुपोषित भारत के निर्माण की दिशा में उत्तर प्रदेश ने अनुकरणीय कार्य किया है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने प्रदेश में महिला सुरक्षा और पोषण के अंतर्संबंधों को रेखांकित किया, वहीं उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षण सामग्री, खिलौनों और गतिविधि पुस्तिकाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रदेश के अनेक मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

आधी आबादी को हो महिला सशक्तिकरण का वास्तविक एहसास: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को जनपद वाराणसी में आयोजित 'कामकाजी महिला सम्मान समारोह' में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, रसोइयों, सफाई मित्रों और आशा वर्करों सहित विभिन्न कामकाजी महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण केवल नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आधी आबादी को इसका वास्तविक धरातल पर अनुभव होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में ऐसा सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे बेटियां घर की चौखट से निकलकर अपने सपनों की मंजिल हासिल कर रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक राजधानी काशी के सर्वांगीण विकास हेतु प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 12 वर्षों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग को नई योजनाओं व आधुनिक तकनीकों से जोड़कर काशी को नई वैश्विक पहचान दिलाई गई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय थी, जिससे उनके सपनों और कदमों पर रुकावटें आती थीं। वर्ष 2017 के बाद सरकार ने मिशन शक्ति के जरिए सुरक्षा का सुदृढ़ वातावरण तैयार किया। पहली बार मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित हुए, महिला बीट प्रणाली लागू की गई और हेल्पलाइन 1090 व 181 को अत्यधिक प्रभावी बनाया गया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 में पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या मात्र 10 हजार थी, जो अब बढ़कर लगभग 45 हजार हो चुकी है तथा पुलिस भर्तियों में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त बदायूँ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी तथा गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर तीन महिला पीएसी बटालियनों की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विश्वस्तरीय हाईवे, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और बेहतर कनेक्टिविटी ने महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, बाजार और कार्यस्थलों की दूरी को सुगम व सुरक्षित बनाया है। भारतीय संस्कृति के मूल भाव 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता' को धरातल पर उतारते हुए जन्म से लेकर शिक्षा, विवाह और रोजगार तक बेटियों के स्वावलम्बन के लिए योजनाएं संचालित हैं।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से स्नातक तक बेटियों को 25 हजार रुपये का संबल दिया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख से अधिक बेटियों का सम्मानपूर्वक विवाह संपन्न कराया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार कक्षा 12 तक किया गया है, अटल आवासीय विद्यालयों में आधी सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं तथा सैनिक स्कूलों में बेटियों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। युवाओं को टैबलेट-स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं और शीघ्र ही स्नातक अंतिम वर्ष की 50 हजार मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश की 8 हजार न्याय पंचायतों में से 4 हजार महिला डिजिटल उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और ओडीओपी के जरिए पारंपरिक शिल्पों को नई पहचान मिली है, जिसमें वस्त्र व हथकरघा उद्योग में 80 प्रतिशत से अधिक भागीदारी महिलाओं की है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जिनमें 28 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। विभिन्न मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों से 4 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं तथा 24 हजार से अधिक स्टार्टअप्स में लगभग आधे स्टार्टअप्स का संचालन महिलाएं कर रही हैं। परिणामस्वरूप प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक घरौनी वितरण से महिलाओं को आवासीय संपत्तियों का मालिकाना अधिकार मिला है, जबकि 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा लागू की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 9 वर्षों की यह यात्रा भयमुक्त वातावरण से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की यात्रा रही है। उन्होंने दृढ़ता के साथ स्पष्ट किया कि सरकार समाज को बांटने वाली राजनीति और माफिया तंत्र के सामने कभी नहीं झुकेगी तथा विकास व सुरक्षा की गारंटी डबल इंजन सरकार पूरी मजबूती से निभाती रहेगी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित